



## संपादकीय

# सुरक्षा कवच में छिद्र

## फसल बीमा का पूरा लाभ मिले किसान को

एक दशक पूर्व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई इस मकसद से शुरू की गई थी कि देश के अन्नदाता के हित तमाम ऊंच-नीच में सुरक्षित रह सकें। सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का त्रास पीढ़ी-दर-पीढ़ी भुगतते किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया था। मकसद था किसान हिलों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन जिस पीएमएफबीवाई के आज दस साल पूरे हो रहे हैं, वह आज एक चुनौतिपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। जिसके वास्तविक लाभों पर मंथन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

दरअसल, मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में खेती-किसानी में एक बड़े जोखिम को कम से कम करने का प्रयास किया था। फसल बीमा से किसानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दरअसल, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को जलवायु और बाजारों की बढ़ती अस्थिरता से बचाना था। लेकिन विडंबना यही है कि इस योजना के अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल पाये। बल्कि यह योजना बीमा कंपनियों के लिये दुधारू गाय बनकर रह गई। यहां तक कि भाजपा शासित राज्यों हरियाणा और राजस्थान से मिली प्राथमिक जानकारी से पता चला है कि इस योजना का लाभ किसान के बजाय बीमा कंपनियों का सकल प्रभुत्व उठा रही हैं। वर्ष 2023 से 2025 के बीच, हरियाणा में बीमा कंपनियों ने पीएमएफबीवाई के तहत 2,827 करोड़ रुपये का सकल प्रीमियम एकत्र किया था। लेकिन जहां तक फसलों को हुई क्षति के लिये दावों के भुगतान का प्रश्न है, केवल 731 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। यानी बीमा कंपनियों को सीधे-सीधे 2,000

करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है। इतना ही नहीं, शेष देश के आंकड़े भी कम चौकाने वाले नहीं हैं। केवल तीन वर्षों में ही 82,015 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम के रूप में एकत्रित किए गए। जबकि किसानों को क्षतिपूर्ति के लिये मात्र 34,799 करोड़ रुपये ही वितरित किए गए। बीमा कंपनियों को 47,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ। यह विडंबना ही है कि जिस महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना को किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये लाया गया था, वो बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी का जरिया बन गई है। निश्चय ही देश की खाद्य सुरक्षा व किसान हित में योजना को बीमा कंपनियों के मुनाफे का जरिया बनने से रोकने की जरूरत है। बल्कि फसल बीमा योजना के क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसान को अधिक लाभ मिल सके। हरियाणा के कुछ हिस्सों में किसानों के दावों में की जाने वाली देरी अथवा किसानों के दावे खारिज किए जाने के खिलाफ धरना देने की बात भी सामने आई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में फसल बीमा योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं।

अनुचित लाभ उठाने के लिये जाली फॉर्म और फर्जी बैंक खातों का उपयोग किया गया है। निस्संदेह, यदि बीमा कंपनियां सिर्फमुनाफा कमाती रहीं और किसान को योजना का लाभ पर्याप्त रूप से न मिला, तो निश्चित रूप से किसानों का इस योजना से भरोसा उठ जाएगा। ऐसे में यदि किसान अनियमित मौसम की मार, बढ़ते कर्ज के बोझ और नौकरशाही की बाधाओं से जूझते रहे तो वे योजना का लाभ पाने से वंचित हो जाएंगे। निस्संदेह, पीएमएफबीवाई किसानों के हितों को संरक्षित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिये सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली को एकीकृत करने का प्रयास किया गया था। इतना ही नहीं, पीएमएफबीवाई के अंतर्गत किफायती प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारी सब्सिडी के साथ दिया जाता है। निर्विवाद रूप से प्रीमियम का बड़ा हिस्सा जनता के पैसे से भरा जाता है। जब प्रीमियम व दावा अनुपात विरोधाभासी हो तो करदाताओं के पास जवाबदेही मांगने का पूरा अधिकार है। निस्संदेह ऐसे वक में जब पीएमएफबीवाई ग्यारहवें वर्ष में प्रवेश कर रही है, सुधारों से इसका भविष्य तय होना चाहिए। पारदर्शी ऑडिट, दावों का तेजी से निपटान, बीमा कंपनियों की कारगुजारी पर कड़ी निगरानी की जरूरत व इस प्रक्रिया में किसानों का अधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

# नये परिदृश्य में हसीना के प्रत्यर्पण का यक्ष प्रश्न



पुष्परंजन

भारत ने आम तौर पर शरणार्थियों को वापस न भेजने की नीति अपनाई हुई है। इसी नीति के तहत, दलाई लामा जैसे प्रमुख राजनीतिक शरणार्थियों को ऐतिहासिक रूप से संरक्षण दिया गया है। हालांकि, भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

शेख हसीना, जो 5 अगस्त, 2024 को हिंसक प्रदर्शनकारियों से जान बचाते हुए ढाका से गाजियाबाद के लिए एक सिक्रेट फ्लाइट से भागी थीं, अभी फांसी से दूर हैं, और नई दिल्ली निर्वासन में रह रही हैं। शेख हसीना का सवाल विक्रम और बेताल की तरह मोदी सरकार के कंधे पर सवार है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को ‘एआई समिट’ में उपस्थित रहना था, इसलिए तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने ढाका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को भेजा। बांग्लादेश की तरफ से उन्हें सौंपने के बार-बार अनुरोध के बावजूद भारत में हसीना की मौजूदगी पिछले 18 महीनों में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह रही है।

भले ही भारत, ढाका के साथ ‘पोस्ट हसीना पार्टनरशिप’ बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा, कि वे ऐसे हालात की कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सामना करने के लिए बांग्लादेश को सौंप दे। ढाका रह चुके भारत के पूर्व हाई कमिश्नर पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा,

‘नई दिल्ली उन्हें मौत की तरफकैसे धकेल सकती है?’

हसीना, बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं, वो शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। शेख हसीना कोई पहली बार भारत में शरणगत नहीं हुई हैं। 15 अगस्त, 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में उनके धानमंडी स्थित घर पर मिलिट्री तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनकी पत्नी, तीन बेटे और दूसरे रिश्तेदार मारे गए थे। उनकी दो बेटियां संयोगवश बच गयीं, जो घटना के समय जर्मनी में थीं। उनमें एक शेख हसीना और दूसरी शेख रेहाना थीं। हसीना के पास अपने पति एमए वाजेद मियां के साथ भारत में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

वर्ष 1975 से 1981 तक वे सभी दिल्ली के पंडारा रोड में एक नकली पहचान के साथ रहे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार, हसीना के ‘निर्वासन पार्ट-टू’ को लेकर दुविधा में है। हसीना ने 2022 के इंटरव्यू में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद के पलों को याद करते हुए कहा, ‘मिसेज इंदिरा गांधी ने तुरंत हसीना की मौजूदगी पिछले 18 महीनों में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह रही है।’

हसीना ने 2022 में न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, ‘इंदिरा गांधी ने हमारे लिए सारे इंतज़ाम किए। मेरे पति के लिए नौकरी भी।’ दिल्ली में हसीना पहले 56 रिंग रोड, लाजपत नगर-3 में रहती थीं, फिर दिल्ली के पंडारा रोड के घर में शिफ्ट हो गईं। छह साल बाद, 17



मई, 1981 को, हसीना बांग्लादेश लौटीं। वापसी के बाद देश पर कब्ज़ा कर चुकी मिलिट्री सरकार के खिलाफ एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की शुरुआत की। करणान के आरोपों में जेल के बावजूद, हसीना डडी रहीं। आखिरकार, 1996 में शेख हसीना सत्ता में आई, और पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं।

लेकिन उस कालखंड से इस समय अलग परिस्थितियां हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश के सन्दर्भ में अपनी पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी की राह पर चले ज़रूर, मगर इसके अंजाम का आकलन मोदी के रणनीतिकार सही से नहीं कर पाए। वर्ष 2013 में भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी। और 2016 में इसमें बदलाव किया गया था, जो कम से कम एक साल की जेल की सज़ा वाले अपराधों के दोषी या अभियुक्तों की अदला-बदली का अनुमति देती है। इसमें आतंकवाद, ट्रैफिकिंग और ऑर्गनाइज़्ड क्राइम जैसे अपराध शामिल हैं, लेकिन यदि कोई राजनीतिक कैदी है, तो उसके प्रत्यर्पण से मना करने की सहूलियत भी संधि में है। 11 पेज की संधि के अनुच्छेद 6-7 और 8 को ध्यान से पढ़ा जाये, तो शेख हसीना को

आपराधिक धाराओं से भी छूट मिल जाती है। भारत इन्हीं धाराओं के आधार पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण से मना करने की स्थिति में है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और उनके समकक्ष डॉ. मोहिनुद्दीन खान आलमगीर अभी जीवित हैं।

बहरहाल, 17 नवंबर, 2025 को 453 पेज के फैसले में, बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने शेख हसीना और दो सह-आरोपियों को दो अलहदा मामलों में मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें पिछले साल 5 अगस्त को ढाका के चंखारपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप संख्या 4 के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी। आरोप संख्या 5 के तहत, आरोपियों पर उसी दिन अशुलिया में छह छात्र प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आरोप था, जिनमें से पांच को बाद में जला दिया गया था, जबकि छठे को कथित तौर पर जिंदा रहते हुए आग लगा दी गई थी। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जो सरकारी

गवाह बन गए थे, को इस मामले में पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। भारत का कहना है, कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश के आग्रह की जांच कर रहा है।

क्या भारत ने पहले कभी किसी राजनीतिक शरणार्थी का प्रत्यर्पण किया है? भारत ने आम तौर पर शरणार्थियों को वापस न भेजने की नीति अपनाई हुई है। इसी नीति के तहत, दलाई लामा जैसे प्रमुख राजनीतिक शरणार्थियों को ऐतिहासिक रूप से संरक्षण दिया गया है। हालांकि, भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपराधिक मामलों या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यर्पण या निर्वासन का उसका अपना इतिहास रहा है।

वर्ष 1959 से भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे रखी है। चीन ने उसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन प्रत्यर्पण की मांग पूरी नहीं हुई। चीन से हमारे संबंध दोस्ती और कुश्ती वाले रहे हैं। चीन से गलवान-देपसांग झड़प भी हुई, तो उभयपक्षीय व्यापार एकदम से रुक नहीं गया। तो क्या हम बांग्लादेश से चीन जैसा सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं, या फिर शेख हसीना की ‘कूटनीतिक बलि’ दे दी जाएगी? यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है, कि शेख हसीना किसी थर्ड कंट्री में शरण चाहेंगी। शेख हसीना की कोमल पर कोई तीसरा देश क्यों अपने सम्बन्ध तारिक रहमान सरकार से खराब करेगा? बीएनपी को इतना बड़ा जनकण्ठ सहानुभूति वोट, और शेख हसीना शासन में हुए सितम की वजह से मिला है। तारिक रहमान हर हाल में शेख हसीना से पुराना स्कोर सेटल करना चाहेंगे।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

# समृद्धि का अमृत तो मिला पर प्रदूषण का विष कौन पीरगा?

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब देवों और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र-मंथन किया था तो अमृत से पहले हलाहल नामक भीषण विष निकला था। उस विष से समस्त सृष्टि के विनाश का संकट खड़ा हो गया था। तब भगवान शिव ने करुणवश उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए।

आज के युग में हम एक बार फिर मंथन कर रहे हैं। यह प्रकृति के संसाधनों का मंथन है। हम अपनी सुख-सुविधाओं और अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के गर्भ से आकाश तक, हर प्राकृतिक संसाधन को मथ रहे हैं। इससे हमें आर्थिक समृद्धि और तकनीकी अमृत तो मिल रहा है, पर इससे प्रदूषण का विष भी निकल रहा है।

विकास की हमारी अंधी दौड़ ने न केवल हवा को जहरीला और जल को प्रदूषित किया है, बल्कि मिट्टी को भी बहुत हद तक बंजर बना दिया है। धरती का बढ़ता तापमान और अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। विडम्बना यह है कि हम प्राकृतिक संसाधनों को इतनी निर्यतना और तेजी से मथ रहे हैं कि प्रकृति को स्वयं को सम्भालने और पुनर्जीवित



करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है।

आज मानवता पृथ्वी की क्षमता से कहीं अधिक उपभोग कर रही है। यह अतिरिक्त उपभोग ही वह विष है, जो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन और कचरे के रूप में चुल रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज के इस विष को कौन पीएगा?

क्या हम किसी चतुर्त्कार की प्रतीक्षा करें कि कोई आएगा और हमारे द्वारा फैलाए गए इस प्रदूषण को सोख लेगा?

विज्ञान और तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी या नीति तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक हम धरती की सीमाओं में न जीएं और विष पैदा करना बंद न कर दें।

मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति को अपने हिस्से का थोड़ा-थोड़ा हलाहल पीना होगा। यह विष किसी प्याले में नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली में है। हमें अपनी अधिक पाने की लालसा को अपने कंठ में

ही रोकना होगा ताकि वह धरती के भीतर तक न पहुंचे। जब समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का यह विष पीएगा, तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत सुरक्षित रह पाएगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पृथ्वी सीमित है और यह हमेशा सीमित ही रहेगी, चाहे हमारा विज्ञान और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी भी प्रगति क्यों न कर ले। हकीकत में, संसाधनों की कमी को समझना मनुष्यों के लिए बहुत ही सहज

और स्वाभाविक है जब हमारी आय सीमित होती है, तो हम अपने खर्चों को स्वतः ही सीमित कर लेते हैं। यदि हमारे पास पांच सीटों वाली कार है, तो हम उसमें दस लोगों को बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करते। हम हर दिन क्षमता के आधार पर निर्णय लेते हैं, फिर पृथ्वी के संदर्भ में हम इस बुनियादी सत्य को क्यों भूल जाते हैं?

हमें समझना होगा कि पृथ्वी का आकार निश्चित है और यह समय या तकनीक के साथ नहीं बढ़ रहा है। इसके संसाधन भी सीमित हैं। फिर ऐसा कैसे है कि हमारा उपभोग और मांग लगातार बढ़ती जा रही है? यह अहसास कि हम एक सीमित धरती पर रह रहे हैं, समाधान की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचान लेंगे, तभी हम सही मायने में समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। यहां यह समझना भी अनिवार्य है कि यह समस्या हम सभी के उपभोग से पैदा हुई है, इसलिए समाधान का हिस्सा भी हम सभी को बनना होगा।

यदि हम अपनी आदतों को सुधार लें और ‘अफोर्ड’ करने की क्षमता होने के बावजूद प्रकृति के लिए ‘अवॉइड’ करना सीख जाएं, तो हम इस विष को फैलने से रोक सकते हैं। विकास का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि संतुलन होना चाहिए। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

# प्रगतिशील दृष्टि से देखें फिल्मों में अभित्यक्ति

रोहित कौशिक

लीक से हटकर जो किताबें और फिल्में होती हैं, वे हमारे चेतना-तंतुओं को झकझोरने का काम करती हैं। ऐसी किताबें और फिल्में अनेक तरह के सवाल तो उठाती ही हैं, कई पारम्परिक धारणाओं को भी तोड़ती हैं। क्या हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर लोगो की भावनाएं कुछ ज्यादा ही आहत नहीं होने लगी हैं? ताजा मामला है ‘घूसखोर पंडट’ फिल्म का। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म का टाइटल बदलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से यह फैसला दिया है। इसलिए इस फैसले पर कोई सवाल नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग इस मुद्दे पर कोई सवाल खड़े होते हैं। एक फिल्म का टाइटल यदि किसी समाज की भावनाएं आहत कर दे तो यह सवाल तो उठेगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी क्या हम एक प्रगतिशील समाज बना पाए हैं?

एक काल्पनिक फिल्म और काल्पनिक किताब यदि किसी समाज की भावनाएं आहत करने की हिम्मत रखता है तो यह सवाल भी उठेगा कि क्या हमारी भावनाएं भी तो काल्पनिक नहीं हो गई हैं। यह केवल ब्राह्मण समाज का मामला नहीं है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर किसी जाति या किसी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती रहती हैं। बहरहाल, अब इस फिल्म



का टीजर और उससे जुड़ी सभी प्रमोशनल सामग्री नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब से हटा ली गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि इस तरह के टाइटल और फिल्म सामग्री ने न केवल समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ सकता है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को भी खतरा हो सकता है।

हमारे देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने इस देश के विकास में अपना योगदान दिया है। जिस तरह अन्य जातियों और समाज के लोगों ने देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसी तरह ब्राह्मण समाज के लोगों के योगदान को भी भूला नहीं जा सकता। इस फिल्म के

जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। इस दौर में हमारी भावनाएं इतनी जल्दी क्यों आहत होने लगती हैं? निश्चित रूप से यह समाज लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है लेकिन क्या एक पढ़े-लिखे समाज में हमारी मानसिकता भी बड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या संकुचित मानसिकता से वास्तव में हम प्रगतिशील समाज के दायरे में आ पाएंगे? इस दौर में क्या हमारी समझ छोटी हो गई है या फिर हम जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं? कभी कोई किताब हमारी भावनाएं आहत कर देती है तो कभी कोई फिल्म हमारा अपमान कर देती है। क्या वास्तव में हम 21वीं सदी का समाज कहलाने लायक हैं?

हर जाति और धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अगर अच्छाई और बुराई को हम किसी एक जाति या धर्म से जोड़कर देखने लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। भ्रष्टाचार करने वाला ईसाई किसी भी जाति या धर्म में हो सकता है। अगर किसी जाति या समाज का एक या कुछ ईसाई भ्रष्टाचारी हैं तो इस आधार पर वह पूरा समाज भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। दरअसल, इस दौर में शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ। यह समाज पहले से अधिक पढ़ा-लिखा और प्रगतिशील है।

निःसंदेह, प्रगतिशील दौर में जाति कमजोर होनी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस दौर में जाति और मजबूत हो गई है। जाति आधारित संघटन भी मजबूत हो रहे हैं। यही कारण है कि हर जाति अपने अपमान की बात करने लगी है। हमें यह

समझना होगा कि किसी एक क्रियाकलाप से भला पूरी जाति का अपमान कैसे हो सकता है। इस दौर में भी मजबूत होती जाति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज में वैमनस्य पैदा कर रही है। आए दिन कहीं न कहीं जाति के अपमान के मुद्दे पर हंगामा होता रहता है। सवाल यह है कि क्या एक पढ़े-लिखे समाज में इस तरह की मानसिकता उचित है? निश्चित रूप से एक पढ़े-लिखे समाज से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

आलोचना होती है, भारतीय समाज अभी तक भी किताबों को पढ़ने और फिल्मों को देखने की प्रगतिशील सोच की समझ विकसित नहीं कर पाया है। लीक से हटकर जो किताबें और फिल्में होती हैं, वे हमारे चेतना-तंतुओं को झकझोरने का काम करती हैं। ऐसी किताबें और फिल्में अनेक तरह के सवाल तो उठाती ही हैं, कई पारम्परिक धारणाओं को भी तोड़ती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम अपने अंदर झांकने के बजाय ऐसी किताबों और फिल्मों को ही कंठधरे में खड़ा करने लगते हैं। यही कारण है कि भावनाएं आहत होने के नाम पर या फिर समाज का अपमान होने के नाम पर किताबों और फिल्मों पर रोक लगाने की मांग अक्सर उठती रहती है। इस दौर में हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, वह हमें अंधकार में धकेल रही है। अभी मानसिकता को बदलकर ही भारतीय समाज इस अंधकार को दूर कर सकता है।

## अमेरिका से ट्रेड डील

पीयूष गोयल के मुताबिक ट्रेड डील में रूसी तेल का मुद्दा नहीं है। इसलिए इस पर विदेश मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। विदेश मंत्री गोयल से पूछने की सलाह दे चुके हैं। प्रधानमंत्री से तो स्पष्टीकरण की अपेक्षा ही नहीं है।

अमेरिका से ट्रेड डील में रूसी तेल के मुद्दे को शामिल करने से भारत को आर्थिक के साथ-साथ प्रतिष्ठा का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री इसकी जवाबदेही एक दूसरे पर टालने की जुगत में दिखे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक उन्होंने जो डील की, उसमें यह ट्रेडकर जो किताबें और फिल्में होती हैं, वे हमारे चेतना-तंतुओं को झकझोरने का काम करती हैं। ऐसी किताबें और फिल्में अनेक तरह के सवाल तो उठाती ही हैं, कई पारम्परिक धारणाओं को भी तोड़ती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम अपने अंदर झांकने के बजाय ऐसी किताबों और फिल्मों को ही कंठधरे में खड़ा करने लगते हैं। यही कारण है कि भावनाएं आहत होने के नाम पर या फिर समाज का अपमान होने के नाम पर किताबों और फिल्मों पर रोक लगाने की मांग अक्सर उठती रहती है। इस दौर में हमारे समाज में जाति और धर्म के नाम पर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, वह हमें अंधकार में धकेल रही है। अभी मानसिकता को बदलकर ही भारतीय समाज इस अंधकार को दूर कर सकता है।

ले, इसकी निगरानी अमेरिका के तीन मंत्री करेंगे। भारत सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने इस अमेरिकी एलान का खंडन नहीं किया। उल्टे मंत्री इसकी जवाबदेही दूसरे पर टालते दिखे हैं। इसलिए इसे ट्रेड डील का हिस्सा मान लिया गया है और बाजार में उसका असर दिखने लगा है। पहली मार गुजरात के वाडीनगर में स्थित नायरा रिफाइनरी पर पड़ती दिखी है।

रूस की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रोसेनफ्त को इसमें सबसे बड़ी शेयरहोल्डिंग है। इसमें अधिकतर रूस से आए कच्चे तेल का शोधन किया जाता है। लेकिन अब अमेरिका से ट्रेड डील के बाद इस रिफाइनरी का चलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि रोसेनफ्त के शेयर खरीद कर कोई भारतीय कंपनी इसकी मालिक बनेगी और फिर वह अन्य स्रोतों से आए तेल का शोधन करेगी।

अनुमान है कि यह तेल अधिकांशतः अमेरिका से आएगा। मगर यह महंगा सौदा है। अमेरिका से तेल ऊंचे भाव में मिलेगा। परिवहन खर्च पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। उधर अमेरिकी दबाव में आने के कारण तेली कर कहा कि भारत रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर राजी हुआ है। यह भी बताया कि भारत कहीं चुरी-छिपे तेल ना खरीद जरूरत पड़ी है।







# ‘इंडस्ट्री में हमेशा सम्मान मिला’ सनी लियोनी ने बताया कैसे की ‘कैनेडी’ की तैयारी

**सनी लियोनी अनुराग कश्यप की आगामी फिल्म ‘कैनेडी’ में एक अलग अवतार में नजर आएंगी। अब अभिनेत्री ने फिल्म, अपने किरदार और अपनी बायोग्राफी को लेकर बात की। जानिए अनुराग कश्यप को लेकर एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा.....**

सनी लियोनी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘कैनेडी’ को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। यह वही फिल्म है जो 2023 में कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। फिल्म को कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में काफी सराहना भी मिली है। अब फिल्म भारत में रिलीज को तैयार है।

सनी लियोनी ने कहा जब मैं अपने सफर पर नजर डालती हूं, तो लगता है कि इतने वर्षों बाद भी ‘कैनेडी’ मेरे भीतर कहीं न कहीं जिंदा है। मुझे बहुत खुशी है कि यह फिल्म अब ऑडियंस के सामने आने वाली है। मैं इतने समय से इसे अपने भीतर लेकर चल रही थी। अब इसे लोगों तक पहुंचते देkhना मेरे लिए बेहद भावुक क्षण है।

चाली का किरदार अपने आप में एक रहस्य जैसा था। इसमें कई परतें और कई तरह की ऊर्जा थीं। मुझे उसे खुद में उतारना था ताकि वह मेरा हिस्सा बन जाए। निर्देशक अनुराग कश्यप की आवाज और

उनका समझाने का तरीका मेरे लिए मार्गदर्शन बनता था। हम रोज काम शुरू करने से पहले पढ़ते और सुनते थे। फिर समझते और कुछ नया खोजते थे।

### फिल्म का अनुभव सबसे खास रहा

अनुराग सर ने मुझसे कहा था कि चाली की हंसी बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसी वह कल्पना कर रहे हैं। इस हंसी को अपने भीतर लाना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे हर जगह हंसना पड़ता था। कार और लिफ्ट में भी हंसना पड़ता था। सेट पर इतने लोग होते थे कि वे मुझे देखकर सोचते थे कि मैं क्यों हंस रही हूं। कई बार मुझे लगता था कि लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे।

सच कहूं तो यह बात मुझे और मजेदार लगती थी क्योंकि मुझे मस्ती करना पसंद है और यह चाली वाली मस्ती एक अलग तरह की आजादी देती थी। धीरे-धीरे वह हंसी मेरे भीतर बस गई। इससे मैं चाली को गहराई से महसूस कर पाई। ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती।

### अनुराग कश्यप के सामने अपनी बात रखना आसान होता है

अनुराग कश्यप के साथ काम करते हुए मैं हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। बाहर से लोग सोचते हैं कि वह गंभीर या कठोर होंगे। लोग उनकी फिल्मों या कहानियां देखकर उनके बारे में एक इंटेंस पर्सनालिटी की छवि बना लेते हैं। पर असल में वह बहुत नरमदिल व्यक्ति हैं। उनके सामने बैठकर बात करते समय हमेशा लगता था कि मेरी बात को महत्व मिल रहा है।

हर कलाकार को यह एहसास नहीं मिलता कि उसे सुना जा रहा है। उन्होंने मुझे वही बनने दिया जो मैं उस पल बनना चाहती थी। यही वजह है कि उनसे जुड़ा हर अनुभव मेरे दिल में खास जगह रखता है।

## ‘दुनिया मेहनत नहीं देखती’

**राजकुमार राव इन दिनों अपने बड़े हुए वजन को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। अब पत्नी प्रलेखा ने राजकुमार का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया है। जानिए एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा.....**

हाल ही में अभिनेता राजकुमार राव को उनके बड़े हुए वजन को लेकर ट्रोल् किया गया था। लोगों ने उन्हें बूढ़ा तक कह डाला था। इसके बाद बीते दिन राजकुमार राव ने आलोचकों को जवाब देते हुए वजन बढ़ाने का कारण भी बताया था। अब अभिनेता की पत्नी व एक्ट्रेस प्रलेखा ने राजकुमार राव का सपोर्ट किया है। साथ ही उन्होंने ट्रोल्स पर भी निशाना साधा है।

### प्रलेखा ने किया राजकुमार का सपोर्ट

प्रलेखा ने राजकुमार राव की एक पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर करते हुए अभिनेता का सपोर्ट किया है। राजकुमार राव पर गवें जताते हुए प्रलेखा ने स्टोरी पर अपने नोट में लिखा, ‘आप पर बहुत गर्व है। आप हर फिल्म प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ देते हैं। दुनिया उस प्रोसेस और मेहनत को नहीं देखती, जो एक एक्टर के किरदार को बनाने में लगता है। आखिरी नतीजा हमेशा आसान दिखता है। नजर आने वाले सारे फेम और ग्लैमर के पीछे, एक एक्टर की जिंदगी खून, पसीने, आंसुओं और पर्सनल लाइफ के त्याग से भरी होती है।’

### ‘निकम’ फिल्म के लिए राजकुमार ने बढ़ाया वजन

हाल ही में राजकुमार राव एक इवेंट में शामिल हुए थे। जहां उनके बदले हुए लुक को देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल् किया था और बूढ़ा बता दिया था।

**राजकुमार राव के समर्थन में उतरीं पत्नी प्रलेखा**

इसके बाद राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया था।

इसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म ‘निकम’ के लिए 9-10 किलो वजन बढ़ाया है।

इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की और पिज्जा, मिठाई, आलू परांठे और बिरयानी सहित हाई कैलोरी वाले खाने का सेवन किया।

एक्टर ने पोस्ट में ये भी बताया था कि उन्हें प्रोस्थेटिक मेकप पसंद नहीं है, इसलिए जहां तक संभव होता है वो अपने शरीर पर मेहनत करते हैं।

पोस्ट में राजकुमार राव ने अपनी उन पिछली फिल्मों का भी जिक्र किया, जिनके लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। इसमें ‘बोस’, ‘श्रीकांत’ और ‘ट्रेड’ जैसी फिल्में शामिल हैं।

### इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में मिली एंट्री

उस वक्त जो खुशी मिली थी उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वहां मुझे एक छोटा सा कागज मिला था, जिसमें मेरी सीट का नंबर लिखा था। वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवॉर्ड था। उस टिकट को मैं आज भी एक किताब के भीतर संभाल कर रखा है।

मेरी बायोपिक ‘करणजीत कौर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी’ 2018 में रिलीज हुई थी। उस वक्त प्रोडक्शन के कुछ मसलों के चलते इसका दूसरा भाग नहीं आ सका पर मेरी अपनी कहानी में अब भी बहुत सारे अध्याय बाकी हैं, जिन्हें दुनिया ने न देखा न सुना है। मौका मिला तो मैं अवश्य अपना जीवन फिर से खोलकर रखना चाहूंगी।

### सफलता की सबसे बड़ी परिभाषा, अवॉर्ड्स कितने मायने रखते हैं

मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब आप दूसरों की सफलताएं देखते हैं, तो मन में एक छोटी सी इच्छा उठती है। लगता है कि काश मुझे भी कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें मुझे पहचान मिले। यह भावना हर कलाकार के भीतर होती है और मेरे भीतर भी थी। लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं एक दिन यहां बैठकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में इस तरह बात करूंगी।

15 वर्ष हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस मुकाम पर हूं। मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हर कदम पर मुझे ऊपर उठाते हैं और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानती हूं।

पेशेवर स्तर पर महामारी के बाद इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए। ऑडियंस अब दुनिया भर की कहानियां देखते हैं और कंटेंट को नए नजरिए से समझते हैं। मुझे लगता है कि भारत को वैश्विक सिनेमा की कतार में पहले की तुलना में और मजबूती से खड़ा होना चाहिए।



**नेटफिलक्स की फिल्म में नजर आएंगे राजकुमार राव**

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता आखिरी बार पिछले साल रिलीज हुई फिल्म ‘मालिक’ में नजर आए थे। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके अलावा उनकी आगामी फिल्मों में नेटफिलक्स की फिल्म ‘टोस्टर’ शामिल है। इसमें उनके साथ सान्ना मल्होत्रा और अभिषेक बनर्जी भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में दो बायोपिक ‘निकम’ और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक भी शामिल हैं।

## ‘स्टार को बीमा पॉलिसी समझते हैं मेकर्स’

### मोना सिंह बोलीं- मेरे नाम पर कोई 100 करोड़ की फिल्म नहीं बनाएगा



टीवी की जस्सी के नाम से मशहूर अभिनेत्री मोना सिंह अब इंडस्ट्री की सबसे बिजी अभिनेत्रियों में से एक हैं। वो फिल्मों के साथ-साथ वेब सीरीज में भी लगातार काम कर रही हैं। हाल ही में मोना सिंह नेटफिलक्स की सीरीज ‘कोहरा’ के दूसरे सीजन में नजर आई हैं। लगातार फिल्मों और सीरीज में अहम भूमिकाएं निभाने के बावजूद मोना सिंह का कहना है कि

प्रोड्यूसर्स उनके नाम पर 100 करोड़ रुपये के बजट की फिल्म बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते।

### मुझे पता है मैं क्या नहीं चाहती

न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान मोना सिंह ने अपने करियर के उस मुकाम पर होने की बात की, जहां वह आसानी से प्रोजेक्ट्स को ठुकरा नहीं सकती। अभिनेत्री ने कहा कि यह मेरे द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से ही है कि मैं यहां हूं। मैंने प्रासंगिक बने रहने और अपने सिद्धांतों पर कायम रहने की कोशिश की है। इसलिए मैंने कई प्रोजेक्ट्स को मना किया है। हालांकि, मना करना कभी आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि जीवन में मुझे पता है कि मैं क्या नहीं चाहती। यह स्पष्टता अब मेरे भीतर है।

### पोस्टर पर स्टार लाता है बॉक्स ऑफिस पर पैसा

अभिनेत्री ने आगे कहा कि निर्माता सितारों को एक बीमा पॉलिसी की तरह देखते हैं, ताकि उन्हें अपना पैसा वापस मिल सके। पोस्टर पर

एक स्टार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गारंटी देता है। फिल्म निर्माण आखिरकार एक व्यवसाय है। आप जानते हैं कि आप निवेश कर रहे हैं और आपको उससे कहीं अधिक पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर किरदार सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह जाते हैं। यही सच्चाई है। अगर आप मेरी मुख्य भूमिका वाली 100 करोड़ रुपये की फिल्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है।

### ‘कोहरा 2’ में नजर आई हैं मोना सिंह

वर्कफ्रंट की बात करें तो मोना सिंह हाल ही में नेटफिलक्स की सीरीज ‘कोहरा’ के दूसरे सीजन में नजर आई हैं। सुदीप शर्मा, गुंजित चोपड़ा और दिग्गी सिंसोदिया द्वारा निर्मित और रणदीप झा द्वारा निर्देशित इस ब्राइम थ्रिलर में मोना सिंह मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ बरुण सोबती, रणविजय सिंह, अनुराग अरोरा और पूजा भार्गवी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। सीरीज को क्रािटिक्स और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

## आरुषि चावला द 50 से हुई बाहर महल बना जंग का मैदान

द 50 शो इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है, जिसमें सभी खिलाड़ियों के बीच खतरनाक लड़ाई देखने को मिल रही है। आरुषि चावला को द 50 से एक्विशन ऑर्डर मिला। उनका नाम अनाउंस होने के बाद वह फूट-फूट कर रोने लगीं। महल से बाहर निकलते समय उन्होंने कृष्णा, ऋषि, शीतू, रिधिमा और करण से कहा कि उन्होंने उन्हें गलत समझा है। गेम के दौरान आरुषि के गेम खेलने की जमकर बुराई भी की, जब उन्होंने नेहल चुडासमा को डेंजर जोन में भेज दिया और उन पर शो में दोनों पार्टियों का साथ देने का भी आरोप लगा। उन्होंने अपना बचाव करते हुए



कहा, मैं वैसी नहीं हूं, जो कुछ सोचती है कुछ बोलती है। ये एपिसोड आरुषि के कारण चर्चा में बना हुआ है। आरुषि चावला कौन हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं। यह सवाल हर किसी के दिमाग में चल रहा है। आरुषि एक एक्ट्रेस, मॉडल और डॉंसर हैं। उनका जन्म 1994 में दिल्ली में हुआ था। आरुषि ने माउंट कार्मेल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में वेंकटेश्वर कॉलेज से हायर स्टडीज की, जहां उन्होंने केमिस्ट्री में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की।

2017 में आरुषि डॉस फैकल्टी मेंबर के तौर पर वर्क डॉस क्लू में शामिल हुईं। उसके बाद साल 2018 में उन्होंने अपना खुद का डॉस स्टूडियो शुरू किया। इसके बाद उन्हें पैराशूट, हीरो बाइक, माउंटेन ब्रोज स्ट्रिप्स और पॉन्ड्स जैसे कई एडवर्टाइजमेंट ऑफर किए गए। 2020 में आरुषि ने एमटीवी रोडीज रेवोल्यूशन सीजन 17 में हिस्सा लिया। हाल ही में उन्होंने मिस स्कूबा इंडिया 2025 का टाइटल जीता। वह एक फिटनेस फ्रिक भी हैं, जिन्हें डॉसिंग, पिलेट्स और कई दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज करते देखा जा सकता है। उनका पूरा इंस्टाग्राम उनकी वर्कआउट पोस्ट से भरा पड़ा है। द 50 में एक टेंशन वाला पल पूरे महल में तब झगड़े में बदल गया, जब डेंजर जोन को लेकर हुई अनबन से आरुषि और करण के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। आरुषि ने भेजे जाने के आईडिया का कड़ा विरोध किया और जोर देकर कहा कि उसे बचाने के लिए कोई अलायंस नहीं है और वह एक आसान टारगेट होगी, लेकिन करण पटेल ने उसकी बात को खारिज कर दिया और उसे नेगेटिव कहा। नेहल चुडासमा ने करण का बचाव करते हुए आरुषि को नार्सिस्स्टिक कहा, जबकि रिद्धि डोगरा ने उस पर दोमुंहा होने का आरोप लगाया और उसे सांप तक बोल दिया।

## गर्मियों के दौरान जिम जाने से पहले खाएं ये चीजें, एक्सरसाइज के लिए मिलेगी ऊर्जा

गर्मी का मौसम शरीर को बहुत थका देता है, खासकर अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं। इस मौसम में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में जरूरी नमक की कमी हो सकती है। इसके कारण आपको कसरत करते हुए थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। हालांकि, अगर आप जिम जाने से पहले सही चीजें खाते हैं तो आप खुद को तरो-ताजा रख सकते हैं। जिम जाने से पहले डाइट में ये 5 चीजें शामिल करें।

### केला खाएं

केला प्राकृतिक मिठास, पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। यह आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा दे सकता है, जिससे आप जिम में अधिक समय तक और बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। केला खाने से आपको ताजगी का एहसास भी होगा और यह पाचन स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डालेगा। इसके अलावा इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं



और थकान को दूर करने में मदद करते हैं।

### पानी पीते रहें

शरीर को अच्छी तरह चलाने के लिए पानी पीना सबसे जरूरी है। जिम जाने से पहले और उसके दौरान भरपूर पानी पिएं, ताकि आपका शरीर ताजगी से भरा रहे। पसीना आने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए, जिम से पहले और

दौरान कम से कम 2-3 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा आप नारियल पानी या नींबू पानी भी पी सकते हैं, जो नमक से भरपूर होते हैं।

### हल्का नाश्ता करें

जिम जाने से कम से कम 30 मिनट पहले हल्का नाश्ता करें, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मौजूद हों। आप ओट्स, पोहा, दही या प्रोटीन युक्त सैंडविच का सेवन कर सकते हैं। इससे आपके

शरीर को ऊर्जा मिलेगी और आप थकान महसूस नहीं करेंगे। हल्का नाश्ता करने से आपको ऊर्जा स्तर बढ़ेगा और आप जिम में अधिक समय तक और बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर सकेंगे। इसके अलावा यह पाचन तंत्र पर भी प्रभाव डालेगा।

### तले हुए और भारी भोजन से बचें

जिम जाने से पहले तले हुए और

भारी भोजन का सेवन न करें, क्योंकि ये पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकते हैं और आपको असुविधा हो सकती है। इससे एक्सरसाइज करते समय आपको भारीपन महसूस होगा या उलटी भी आ सकती है। तले हुए भोजन से पेट में जलन और गैस भी हो सकती है, जिससे आपको मनोबल टूट सकता है। इसके बजाय आप फल, सूखे मेवे या हल्का नाश्ता कर सकते हैं, जो आसानी से पच जाते हैं।

### चाय या कॉफी से परहेज करें

जिम जाने से पहले चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको नींद को प्रभावित कर सकती हैं और शरीर में जलन पैदा कर सकती हैं। इससे आपको कसरत करने की क्षमता भी कम हो सकती है। इसके बजाय आप हर्बल चाय, नारियल पानी या नींबू पानी पी सकते हैं, जो बिना किसी नुकसान के ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप गर्मियों में भी जिम जाकर फिट रह सकते हैं।

# विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम- शिक्षा कौशल और रोजगार पर मंथन के लिए ‘शिक्षा संवाद’

डिजिटल नवाचार से उद्योग साझेदारी तक - ‘शिक्षा संवाद’ में उच्च शिक्षा के भविष्य की रूपरेखा तय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर समन्वय को लेकर आज ‘शिक्षा संवाद’ का आयोजन रायपुर के स्थानीय होटल में किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की भागीदारी रही। उच्च शिक्षा विभाग और आईआईटी मद्रास और लिंकन यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त डॉ. संतोष कुमार देवांगन, सीईओ इलेट्स डॉ. रवि गुप्ता, डायरेक्टर आई.सी.एफए.आई. सुधाकर राव, हाई कमिशनर ऑफ सैशेल एच. ई. हरिसोया लालटीआना सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर उपस्थित थे।

विकसित छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार का सेतु, थीम पर आधारित सत्र



में उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने, उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के समायोजन और क्षेत्रीय विकास की प्राथमिकताओं पर विशेष चर्चा हुई। आयोजन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को उद्योग की जरूरतों से जोड़ते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करना है।

विभिन्न सत्रों में नई शिक्षा नीति, कौशल उन्नयन, उद्योग-शिक्षा साझेदारी, स्टार्टअप अवसर और भविष्य की रोजगार संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के संवाद से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और युवाओं की रोजगार क्षमता दोनों में सकारात्मक बदलाव आएगा। ‘शिक्षा संवाद’

को छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक और औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

‘शिक्षा संवाद’ के दूसरे चरण में उच्च शिक्षा को डिजिटल, उद्योगोन्मुख और शोध आधारित बनाने पर गहन मंथन हुआ। विभिन्न सत्रों में कुलपतियों, शिक्षाविदों, उद्योग

डिजिटल इनोवेशन से बदलती उच्च शिक्षा

इस सत्र में डिजिटल कैंपस, एलएमएस एवं ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल, एआई आधारित शिक्षण-मूल्यांकन, डेटा आधारित प्रशासन तथा साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने माना कि तकनीक के समुचित उपयोग से पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों में सुधार संभव है।

ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर - शोध, नवाचार और उद्यमिता

अंतिम तकनीकी सत्र में शोध के वर्तमान परिदृश्य, नवाचार केंद्रों की स्थापना, स्टार्टअप प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शोध के व्यावसायीकरण पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने शिक्षा संस्थानों में इनोवेशन कल्चर विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ‘शिक्षा संवाद’ को राज्य में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण, उद्योग सहयोग और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम का समापन सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष कुमार देवांगन के सार-संक्षेप के साथ हुआ। ‘शिक्षा संवाद 2026’ ने राज्य में भविष्य उन्मुख, नवाचार- प्रधान और उद्योग-संरेखित उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने का संकल्प दोहराया।

प्रतिनिधियों और नीति विशेषज्ञों ने भाग लेकर शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के सुझाव प्रस्तुत किए।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए इंडस्ट्रीज-अकादमिक सहयोग

इस सत्र में उद्योग की जरूरतों के

अनुरूप पाठ्यक्रम, इंटरशिप एवं अप्रेंटिसशिप, सेक्टर स्किल कार्टोसिल की भूमिका और परिणाम आधारित शिक्षा पर विचार रखे गए। वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालयों और उद्योग जगत के बीच मजबूत तालमेल से युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर मिलेंगे।

## भारत माता वाहिनी योजना से मजबूत हुआ नशामुक्ति जन आंदोलन, 4 हजार से अधिक व्यक्तियों को मिला पुनर्वास लाभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश में नशामुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरण एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित भारत माता वाहिनी योजना के तहत प्रभावी पहल की जा रही है। राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में 8-सदस्यीय संरचना के साथ कुल 3154 भारत माता वाहिनी समूहों का गठन किया गया है, जो गांव-गांव में नशामुक्ति के संदेश का प्रसार कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा नशामुक्ति के समर्थन में रेली, प्रभात फेरी, जनजागरूकता अभियान, नशा छोड़ने का संकल्प एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक सामाजिक वातावरण निर्मित हुआ है तथा युवाओं में नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

राज्य के 25 जिलों में स्वीच्छक संस्थाओं के माध्यम से 26 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं। इन



केंद्रों में अब तक 4379 नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं से लाभान्वित किया गया है। केंद्रों में चिकित्सकीय परामर्श, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, योग एवं अनुशासित दिनचर्या के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित किया जा रहा है।

जिला बलरामपुर इस अभियान का प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। यहां सक्रिय भारत माता वाहिनी समूहों द्वारा सतत जागरूकता गतिविधियों संचालित की जा रही हैं। साथ ही जिले में संचालित नशामुक्ति केंद्र के माध्यम से अब तक लगभग 478 नशा पीड़ित

व्यक्तियों को उपचार एवं पुनर्वास का लाभ प्रदान किया गया है, जिससे वे पुनः समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जुड़ सके हैं।

उल्लेखनीय है कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार एवं समाज को भी प्रभावित करता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जनभागीदारी आधारित मॉडल को अपनाकर नशामुक्ति अभियान को सशक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत माता वाहिनी योजना के माध्यम से प्रदेश को नशामुक्त, स्वस्थ एवं जागरूक समाज की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं।

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रायगढ़ के धरमजयगढ़ विकासखंड का कुमा ग्राम पंचायत आज ग्रामीण परिवर्तन की एक सशक्त मिसाल बनकर उभरा है। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में कभी पानी की समस्या जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष थी। आज वही गांव जल जीवन मिशन के तहत स्थापित सोलर नल-जल योजना से आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है।

कुछ वर्ष पहले तक ग्राम कुमा में जल संकट सामान्य बात थी। महिलाएं सुबह से लेकर दोपहर तक हैंडपंपों के पास कतार में खड़ी दिखाई देती थीं। गर्मी के दिनों में जलस्तर गिरने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। कई बार पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। इस दैनिक संघर्ष ने महिलाओं का समय, श्रम और ऊर्जा छीन लिया था। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी और परिवार के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर



पड़ता था। गांव के जीवन की रफ्तार पानी की उपलब्धता पर निर्भर थी और यही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी।

गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित नल-जल प्रदाय प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद परिवर्तन की कहानी शुरू हुई। गांव में लगाए गए सोलर पैनलों से संचालित पंप के माध्यम से जल को ऊंची टंकी तक

पहुंचाया जाता है और वहां से पाइपलाइन द्वारा प्रत्येक घर तक नियमित जल आपूर्ति की जाती है। यह व्यवस्था बिजली पर निर्भर नहीं है, इसलिए बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर्यावरण के अनुकूल यह प्रणाली न्यूनतम रखरखाव में दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर रही है।

कुमा में अब हर घर स्वच्छ

और सुरक्षित पेयजल पहुंच रहा है, जिससे गांव की जीवन शैली में स्थायी परिवर्तन आया है। गांव की देवमती बताती हैं कि पहले रोज दो से तीन घंटे बाहर से पानी लाने में निकल जाते थे।

उस समय वे न तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती थीं और न ही किसी और काम के लिए समय निकाल पाती थीं। अब घर पर ही नल से नियमित जल आपूर्ति होने से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर अधिक समय दे रही हैं, स्वसहायता समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी सहभागिता बढ़ी है।

स्वच्छ पेयजल मिलने से परिवार का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और जलजनित बीमारियों में कमी आई है। देवमती गर्व से कहती हैं, अब हमें पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। घर पर ही स्वच्छ पानी मिलने से हमारा जीवन सरल और सुरक्षित हो गया है। बाहर से पानी लाने की बाध्‍यता समाप्त होने से महिलाओं को समय की स्वतंत्रता मिली है। वे इस समय की अब आयवर्धक गतिविधियों और

सामाजिक भागीदारी में लगा रही हैं। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे निर्णय प्रक्रिया में भी अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह परिवर्तन केवल सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से बच्चों की उपस्थिति और स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और घरों में शौचालय के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिला है।

कुमा में ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जो जल आपूर्ति प्रणाली के रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रही है। इससे ग्रामीणों में जिम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता की भावना विकसित हुई है। आज कुमा केवल एक गांव नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक है। यहां बहता स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि विकास, आत्मसम्मान और उज्ज्वल भविष्य की नई धारा प्रवाहित कर रहा है।

## केन्द्रीय पर्यवेक्षकों ने छत्तीसगढ़ में पशुधन योजनाओं का लिया फीडबैक

दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले पहुंचकर योजनाओं का किया निरीक्षण, पशुपालकों से की चर्चा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारत सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय पर्यवेक्षकों का दल 09 से 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहा। इस दौरान वे पशुधन विकास विभाग के केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की छत्तीसगढ़ प्रगति की जानकारी ली केन्द्रीय पर्यवेक्षकों को दल दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले का दौरा कर योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया और पशुपालकों से चर्चा की। केन्द्रीय पर्यवेक्षकों के दल ने छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की सराहना की।



केन्द्रीय दल प्रवास के प्रथम चरण में संचालनालय स्तर पर आयोजित ब्रीफिंग सत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव तथा भारत सरकार के नोडल अधिकारियों द्वारा योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके पश्चात दल ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रशिक्षण गतिविधियों, प्रयोगशालाओं एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों का अवलोकन किया। बालोद जिले के गुण्डदेही एवं डौंडी विकासखंड में बिहान योजना से जुड़ी पशु सखियों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई।

प्रदेश में पशुधन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन कि सराहना की उद्यमिता विकास

कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बकरी पालन इकाइयों, हैचरी यूनिटों तथा दुग्ध संकलन केंद्रों का निरीक्षण कर पशुपालकों से संवाद किया गया। दुर्ग स्थित दुग्ध संघ संयंत्र में दुग्ध प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही पशु चिकित्सालयों एवं मोबाइल वेटेरिनरी इकाइयों में उपलब्ध दवाइयों व उपकरणों की जांच कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रवास के दौरान बालोद जिले में आयोजित जिला स्तरीय पशु मेले में भी दल ने सहभागिता की।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत टीम ने पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय,

अंजोरा, दुर्ग का भ्रमण किया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही मैत्री एवं एवीएफओ रिफ़रर ट्रेनिंग संस्थान तथा शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित ई.टी.टी.-आई.वी.एफ. प्रयोगशाला का निरीक्षण किया गया। जिला बालोद के विकासखंड गुण्डदेही एवं डौंडी में बिहान अंतर्गत कार्यरत 35 पशु सखियों से संवाद कर उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अंतर्गत ग्राम भरदा (दुर्ग) में देवनाथ देशमुख, नवागांव (बेमेतरा) में मनीषा राजपूत तथा बालोद जिले के ग्राम गब्दी एवं बरही में संचालित बकरी इकाइयों की कार्यप्रणाली की

जानकारी ली गई। इसके अलावा बेमेतरा जिले के ग्राम खर्वा एवं सुरहोली स्थित स्काइलाक हैचरी तथा बालोद जिले की एबीस हैचरी यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट अंतर्गत टीम ने उरला (दुर्ग) स्थित छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ प्लांट का भ्रमण कर दुग्ध प्रसंस्करण, पैकेजिंग, घी एवं मक्खन निर्माण इकाई का अवलोकन कर जानकारी ली। बालोद जिले के अर्जुदा तथा बेमेतरा जिले के सरदा एवं मौली भाटा स्थित दुग्ध संकलन केंद्रों का निरीक्षण कर पशुपालकों से चर्चा की गई।

इसी तरह लाइवस्टॉक हेल्थ एवं डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत बेमेतरा जिले में कोल्ड केबिनेट एवं शीत श्रृंखला उपकरणों का निरीक्षण किया। पशु चिकित्सालयों एवं मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट में उपलब्ध दवाइयों, टीकाकरण सामग्री एवं उपकरणों की जांच कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। ग्राम बोहारडीह (बेमेतरा) के उन्नत पशुपालक मानसिंह वर्मा के डेयरी फ़र्म का भी अवलोकन किया गया। दौरे के दौरान जिला बालोद के ग्राम भेंगारी में आयोजित जिला स्तरीय पशु मेला में केन्द्रीय पर्यवेक्षकों की टीम शामिल हुई। टीम ने पशुपालकों से सीधे संवाद कर योजनाओं से मिल रहे लाभ राशि उनके उत्तराधिकारी भ्रिर्तित जानकारी प्राप्त की।

## श्रम विभाग द्वारा घर पहुंच दिलाया जा रहा योजना का लाभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिवारों के बेहदारी के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में श्रम विभाग के अधीन संचालित छठगं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना तहत पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी, नामिनी को योजनांतर्गत देय हितलाभ एक लाख रुपये का लाभ दिया जा रहा है।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में विभाग द्वारा एक सतत अभियान चलाकर इस योजना के अंतर्गत पीडित परिवारों के घर पहुंच जांच कर उनको लाभ दिलाया जा रहा है। निर्माण श्रमिक, असंगठित कर्मकार एवं उनके परिवार को दुःख की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम सोनसायटोला के पंजीकृत श्रमिक स्व. शम्भू राम के मृत्यु उपरांत यह राशि उनके उत्तराधिकारी भ्रिर्तित बाई को उनके खाते में हस्तांतरित



की गयी। योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रूपए, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए कार्यस्थल पर दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर 2 लाख 50 हजार रूपए एवं अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान किया जाता है। योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार न्यूनतम 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदन के

स्वीकृत उपरांत योजना की राशि डी.बी.टी के माध्यम से नामिनी, वैध उत्तराधिकारी के खाते में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना का लाभ लेने हेतु योजना

के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, पंजीकृत श्रमिक एवं नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबंध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा स्थायी दिव्यांगता होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने पंचायत स्तर पर पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य सतत रूप से शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है, इसका उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

**CAR DECOR**  
House Of Exclusive  
Seat Cover,  
Car Stereos Matting &  
Sun Control Film &  
Other Accessories  
Shop No.3 Nafish Tower.  
Opp. Indian Coffee House,  
Akashganga, Bhilai  
Mo.9300771925, 0788-4030919  
K. Satyanarayan

**SAIRAM**  
Mobile Accessories  
मोबाईल शॉप में  
कार्य करने हेतु  
लड़कों की  
आवश्यकता है  
7000415602  
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

**ROCKEY INDUSTRIES**  
FURNITURE PALACE  
Deals in: (Steel & Wooden)  
Luxury & Imported Furniture  
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

**चौरसिया ज्वेलर्स**  
आकर्षक सोने चांदी के अग्रगण्य के निर्माता एवं विक्रेता  
बेन्टवस एवं प्रहलद उपलब्ध यहां  
उचित व्याज दर पर गिरवी रखी जाती है  
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई  
9827938211, 9827171332

**Shri Vijay Enterprises**  
Sanitarywares, Tiles,  
CPVC Pipes &  
Bathroom Fittings etc.  
Supela Market, Bhilai  
PH. 0788-4030909, 2295573



खास खबर



मुख्यमंत्री से महामंडलेश्वर डॉ. गिरी ने की भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी कैलाशनंद गिरि जी महाराज के साथ विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित थे।

छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जयन्ती पर नाटक कल

रायपुर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयन्ती 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे रायपुर नगर पालिक निगम के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में राजधानी शहर रायपुर के जी ई मार्ग में तात्यापारा चौक ( मेजर यशवंत गोरे चौक ) के किनारे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारोही प्रतिमा स्थल के समक्ष उन्हें सादर नमन करने पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। प्रतिमा स्थल के प्रांगण का संधारण और प्रतिमा स्थल प्रांगण सहित उसके आसपास के क्षेत्र की विशेष सफाई, प्रतिमा स्थल की पुष्प सज्जा सहित आवश्यकतानुसार पेयजल की व्यवस्था रायपुर नगर पालिक निगम के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रायपुर नगर पालिक निगम के सम्बंधित जोन क्रमांक 2 के सहयोग से की जायेगी। युवा आयोग द्वारा छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित जाणता राजा का मंमन साईंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इस नाटक को भव्य तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा।

पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय



मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया तथा पर्यटन सुविधाओं का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने झुमका जलाशय में शिकारा पर सवार होकर नौका विहार किया। चारों ओर हरियाली, शांत जलराशि और कमल के फूलों से सजा यह रमणीय स्थल अब एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित विकसित पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली।

श्री साय ने लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया।500 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला यह ओपन थिएटर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नया केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झुमका जलाशय केवल कोरिया जिले की पहचान ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित किया जा सके।

किसानों, महिलाओं और जनजातीय समाज के सशक्तिकरण से समृद्ध होगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री

70 करोड़ से अधिक के 104 कार्यों का लोकार्पण, 85.54 करोड़ के 40 कार्यों का भूमिपूजन-शिलान्यास



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैकुंठपुर में तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन कोरिया महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कोरिया जिलेवासियों को 156 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने 70 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 104 कार्यों का लोकार्पण तथा 85 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक के 40 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास कार्य केवल निर्माण परियोजनाएँ नहीं, बल्कि कोरिया जिले की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और उच्चतर भविष्य के मजबूत आधार स्तंभ हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ को संपन्न और समृद्ध प्रदेश के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। राज्य सरकार ने अपने अधिकांश वादों को अल्प समय में पूरा कर दिखाया है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश की जनता से किए गए विकास संबंधी वादों को भी दो वर्षों के भीतर धरातल पर उतारा गया है।

खनिज और वन संपदा से भरपूर है तथा खनिजों के वैल्यू एडिशन पर विशेष जोर देकर आर्थिक विकास को नई दिशा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोरिया जिले में पर्यटन की बेहद संभावनाएँ हैं। उन्होंने जिले के विकास को गति देने के लिए देवगढ़ छुरी धाम को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने, पुलिस चौकी पोड़ी को थाना का दर्जा देने, पुलिस सहायता केंद्र पंडोपारा को चौकी में उन्नत करने, पीडब्ल्यूडी कार्यालय भवन एवं जिला पुरातत्व कार्यालय स्थापित करने तथा पूलपुर में अधोसंरचना निर्माण एवं ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने जिले में आवागमन सुविधा सुदृढ़ करने के लिए कई सड़क और पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की भी घोषणा की। उन्होंने कोरिया से छिंदिया शिवपुर गांव तक

लगाभग 8 करोड़ रुपये की लागत से पुल-पुलिया निर्माण, कुषहा से घुघरा मार्ग पर 6 करोड़ रुपये की लागत से पुल-पुलिया निर्माण तथा 18 करोड़ रुपये की लागत से सलका बाईपास निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज होगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कोरिया महोत्सव को जिले का विशेष तिहार बताते हुए मुख्यमंत्री को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा मुख्यमंत्री द्वारा जिले की छह महिलाओं को पिंग ई-रिक्षा प्रदान करना सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सांस्कृतिक आयोजन को स्थानीय प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया।

इस अवसर पर विधायक भैयालाल राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 156 करोड़ रुपये के विकास कार्यों से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकार, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी रविकुमार कुर्ते, जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं जिलेवासी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कुम्हार चाक पर गढ़ा दीया, शिल्पकारों से किया आत्मीय संवाद



श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का एक आत्मीय और सहज रूप उस समय देखने को मिला, जब उन्होंने कुम्हार के चाक पर स्वयं मिट्टी का दीया और कलश तद्कर पारंपरिक शिल्प के प्रति सम्मान और जुड़ाव का सशक्त संदेश दिया। सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने वे बैकुंठपुर पहुंचे थे। परिसर में स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसी प्रदर्शनी में सोनहत विकासखंड निवासी शिल्पकार देवी दयाल प्रजापति इलेक्ट्रिक चाक पर दीया और कलश बनाने का सजीव प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री साय उनके स्टॉल पर पहुंचे और कुछ देर तक उनकी शिल्पकला का बारीकी से अवलोकन किया। उत्सुकता बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने स्वयं चाक पर हाथ आजमाने की इच्छा व्यक्त की। शिल्पकार की सहमति से उन्होंने घूमते हुए चाक पर रखी गोली मिट्टी को हाथों से साधा और देखते ही देखते उसे सुंदर दीये का आकार दे दिया। मुख्यमंत्री की सहज कुशलता देखकर स्वयं शिल्पकार भी आश्चर्यचकित रह गए, वहीं उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस क्षण का स्वागत किया।

# सरगुजा क्षेत्र एवं जनजातीय समाज का सर्वांगीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

## सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा

श्रीकंचनपथ समाचार



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता में रखा है।प्राधिकरण के माध्यम से पिछड़े एवं वनांचल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरगुजा क्षेत्र के सर्वांगीण

विकास, जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और क्षेत्र की समृद्धि के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सभी के सहयोग से इस क्षेत्र को प्रगति के नए शिखर पर पहुंचाया जाएगा।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण हेतु 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। क्षेत्रीय

जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 543 विकास कार्यों के लिए 4905.58 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जबकि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 606 कार्यों को भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने

तथा लंबित कार्यों को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने गर्मी के मौसम में पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सोनहत विकासखंड में विद्युतीकरण का कार्य तेजी से जारी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए, ताकि विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनजातीय एवं वनांचल क्षेत्रों के लोगों तक पहुंच सके।

# साय सरकार की नीतियों से बदली बस्तर की तस्वीर, नक्सलगढ़ बन गया राज्य का पर्यटन हब

श्रीकंचनपथ समाचार



रायपुर। कभी नक्सल प्रभावित राज्य की छवि से पहचाना जाने वाला छत्तीसगढ़ अब तेजी से देश के उभरते पर्यटन हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन विरासत और जीवंत आदिवासी संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश अब नई नीतियों और आधारभूत ढांचे के विकास के कारण राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और पर्यटन अधोसंरचना को शीर्ष स्थान दिया गया है। नई औद्योगिक नीति 2024-30 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर निवेशकों को सन्निधि, टैक्स छूट और प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। राज्य में इको-एथनिक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए करोड़ों रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर संभाग

की पहचान उसकी जीवंत परंपराओं से है। गोंड, मुरिया, हल्बा और बेगा जनजातियों की जीवनशैली, पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प और लोकनृत्य पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। पंथी, राउत नाचा, सुवा और कर्मा जैसे लोकनृत्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं।

प्रदेश में स्थित प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल तेजी से पर्यटकों की पसंद बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विविधताओं से देश-विदेश के सैलानियों को लुभा रहा है। चित्रकोट जलप्रपात, जिसे एशिया का नियाग्रा कहा जाता है, एडवेंचर प्रेमियों का पसंदीदा स्पॉट है। जशपुर का मधेश्वर पर्वत आकर्षित करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। रहस्यमयी कुटुमसर गुफाएं एडवेंचर श्रिल प्रदान करती हैं। रामगढ़ की प्राचीन नाट्यशाला राम वनवास स्थल के

रूप में धार्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। ये सभी स्थल राज्य सरकार की विकास योजनाओं से और समृद्ध हो रहे हैं। यूपनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयनित धुडुमारास गांव ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है। इन स्थलों के आसपास सड़क, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार की योजनाओं से पर्यटन केवल भ्रमण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय रोजगार का बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। होम-स्टे, हस्तशिल्प, भोजन और गाइड सेवाओं के माध्यम से आय में वृद्धि हो रही है। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख इको-कल्चरल पर्यटन राज्यों में शामिल हो सकता है।

साय ने बहनों को सौंपी आत्मनिर्भरता की चाबी

उज्ज्वला गैस, पिंग ई-रिक्षा और गाबैज रिक्षा वितरण से महिलाओं को मिला नया संबल

श्रीकंचनपथ समाचार



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कोरिया प्रवास के दौरान कोरिया महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण कर लाभान्वित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में 105 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस योजना से अब इन परिवारों को धुएँ से मुक्ति मिलने के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य के अनुकूल ईंधन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

हितग्राहीमूलक सामग्रियों का किया वितरण

इस अवसर पर स्व-रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 6 आजीविका दीदियों को पिंग ई-रिक्षा (ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस) प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 14 स्वच्छता दीदियों को गाबैज रिक्षा भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल व्यवस्था नहीं



